and the remaining children to be handed over to the Director, Social Welfare Department, Government of West Bengal shortly.

पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के विषय में स्पष्टीकरण

1731. **डा० महेश चन्द्र शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के विषय में अमरीकी समाचार पत्रों की अफवाहों का स्पष्टीकरण देना भारत के लिए जरूरी था; और

(ख) क्या यह भारत की सम्प्रभुता में अमरीकी हस्तक्षेप को स्वीकार करना नहीं है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकब्राल शेरवानी): (क) पाकिस्तान की सीमा के नजदीक पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तथाकथित तैनाती के बारे में वाशिंगटन पोस्ट में छपी खबरों की सरकार को जानकारी है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि ऐसी कहानियों पर टीका-टिप्पणी करके उन्हें महत्व देना सरकार की नीति नहीं है।

तथापि वाशिंगटन पोस्ट की खबरें भारतीय समाचार पत्रों में भी दोहराई गई थी हालांकि वे मिथ्यापूर्ण और भ्रामक थीं।

(ख) अतः 14 जून, 1997 के सरकार के वक्तव्य में यह साफ तौर पर कहा गया था कि पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती नहीं की गई है। सरकार ने अपनी स्पष्ट नीति को भी दोहराया कि पृथ्वी अथवा इस प्रकार के अन्य मामलों पर निर्णय हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में और हमारी सुरक्षा के आशंकाओं के आधार पर लिया जाएगा।

काला आजार और कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिए बिहार में अनुसंधान केन्द्र

1732. **श्री एस० एस० अहलुवालिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार में काला आज़ार एवं कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने हेतु कोई बड़ा अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) जी नहीं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान संस्थान, एक अनुसंधान केन्द्र व अस्पताल पटना में पहले से ही कार्य कर रहा है जिसमें मुख्य जोर काला-आजार पर है। इस समय केन्द्र सरकार का बिहार में काला-आजार के लिए एक बड़े अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत घर पर ही उपचार करने को प्रोत्साहित किया जाता है और केवल जटिलताओं और अल्सर से पीड़ित रोगियों को अस्पताल के अस्थाई वार्डों में दाखिल किया जाता है। बिहार के सभी जिलों में जिला कुष्ठ सोसाइटियां बना दी गई हैं और सभी कुष्ठ रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए सभी जिला कुष्ठ सोसाइटियों को पर्याप्त निधियां प्रदान की गई है।

राज्य के 17 जिलों में अलग से कुष्ठ के क्षेत्रीय स्टाफ की मंजूरी दी गई है और बिहार के 22 जिलों में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ की सहायता से रोगियों को बहु-औषध चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए चल कुष्ठ उपचार केन्द्रों की मंजूरी दी गई है।

Imposition of Heavy Taxes on Tobacco Products

1733. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Medical Association has urged Government to impose heavy taxes on tobacco products to raise money for the tobacco control programme;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to discourage tobacco consumption?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) Pre-budget representations and proposals for levy of heavy taxes on tobacco products so as to discourage the usage are received by the

Government. However, no formal representation has been received from the Indian Medical Association.

(c) Under administrative instructions, tobacco smoking is prohibited in Hospitals, dispensaries and other health care stablishments, educational institutions, Conference Rooms, domestic air flights, air-conditioned chair cars and Air-conditioned sleeper coaches in trains, suburban trains and air-conditioned buses under the control of Government of India. Smoking has also been prohibited in public places and public conveyances in the National Capital Territory of Delhi. In addition the following measures have been taken to discourage consumption of Tobacco:—

(i) As per the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975 it is mandatory to display health warning on all cartons/packets of cigarettes.

(ii) Under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 a warning 'Chewing of tobacco is injurious to health' is mandatory.

(iii) Direct advertisements relating to tobacco or tobacco related products are prohibited on Doordarshan.

(iv) Health Education.

Recommendations of the Task Force on Food Laws

1734. SHRI BANGARU LAXMAN:
SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to stated:

(a) whether recommendations of the Task Force on Food Laws made in 1996, have been considered by Government;

(b) if so, the details of the recommendations made by the Task Force and the areas in which these are likely to be implemented; and

(c) whether these recommendations would have any bearing on the Prevention of Food Adulteration Act, 1954?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) The recommendations of the Task Force on Food Laws have been considered at various levels in Government. The main areas covered by the recommendations relate to upgradation of the infrastructure and laboratory standards required to implement the food laws, standardisation of analytical techniques, licensing of vendors, development of sound industrial practices and strengthening of the Prevention of Food Adulteration (PFA) set up. The recommendations also include ammendments to the existing law like change in the title of the Act; definition of food; providing one counter-part of the sample to the vendor and gradation of penalty clauses. A number of measures recommended by the Task Force have already been included in project for Capacity Building of the organisation for prevention of Food Adulteration which is presently under formulation. Other legal provisions have been proceeded by a Committee of Experts for consideration of Government.

(c) The report was intended to deal with the amendments needed in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, to improve the working of the Act to bring it in harmony with the needs of present day society and generally to rationalise its content.

शिशु आहार और पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच

1735. श्री अजीत जोगी:
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिशु आहार और पेय पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच करती है;